RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 184
दि. 08.04.2026, बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

अल्टीमेटम के साये में टकराव: ट्रंप की चेतावनी पर ईरान का उग्र जवाब, बलिदान की बात ने बढ़ाया वैश्विक तनाव

मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े भू-राजनीतिक टकराव के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जहां शब्दों की जंग किसी भी वक्त वास्तविक संघर्ष में बदल सकती है। एक ओर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump की सख्त चेतावनियां हैं, तो दूसरी ओर Masoud Pezeshkian का उग्र और भावनात्मक पलटवार। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि अब यह केवल कूटनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जनभावनाओं, राष्ट्रीय अस्मिता और संभावित युद्ध के खतरों तक पहुंच गया है।

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दिया गया अल्टीमेटम—जिसमें उसे एक तय समयसीमा के भीतर वैश्विक परिवहन के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने और बातचीत की मेज पर आने को कहा गया—अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने आदेश का पालन नहीं किया, तो उसके बिजली संयंत्रों, पुलों और अहम बुनियादी ढांचे को व्यापक हवाई हमलों के जरिए निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने यहां तक कहा कि यह कार्रवाई इतनी तेज और व्यापक होगी कि कुछ ही घंटों में ईरान की प्रमुख संरचनाएं पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएंगी।

इस कड़े रुख के जवाब में ईरान की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, उसने हालात को और अधिक गंभीर बना दिया है। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने सार्वजनिक रूप से यह दावा किया कि 1.4 करोड़ से अधिक ईरानी अपने देश की रक्षा के लिए जान देने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं भी देश के लिए हर तरह का बलिदान देने को तत्पर हैं। यह बयान केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसे राष्ट्रवादी भावनात्मक आह्वान के रूप में देखा जा रहा है, जो आम जनता को सीधे इस टकराव के केंद्र में ला देता है।

पेज़ेश्कियन का यह संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए सामने आया, जिसने देखते ही देखते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरीं। इस बयान का असर यह हुआ कि ईरान के भीतर एकजुटता और प्रतिरोध की भावना को और बल मिला, वहीं वैश्विक समुदाय में चिंता और भी गहरा गई।

तनाव को और बढ़ाने वाला एक और कदम ईरान के उप खेल मंत्री अलीरेज़ा रहीमी का आह्वान रहा, जिसमें उन्होंने देश के खिलाड़ियों, कलाकारों, छात्रों और आम नागरिकों से बिजली संयंत्रों के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाने की अपील की। इस अपील को एक तरह से 'मानव ढाल' की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य संभावित अमेरिकी हमलों को रोकना या कम से कम उन्हें नैतिक और मानवीय दबाव में लाना है। यह कदम इस बात का संकेत है कि ईरान इस संघर्ष को केवल सैन्य स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रतीकात्मक स्तर पर भी लड़ने की तैयारी कर रहा है।

पूरे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु होर्मुज जलडमरूमध्य बना हुआ है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यहां किसी भी तरह का अवरोध न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका इस मुद्दे को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए है और ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।

व्हाइट हाउस में हुई प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने जिस तरह के बयान दिए, उन्होंने स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि यदि ईरान ने समयसीमा के भीतर समझौता नहीं किया, तो पूरा देश एक ही रात में तबाह हो सकता है। यह बयान केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक स्पष्ट सैन्य संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि अमेरिका किसी भी हद तक जाने को तैयार है।

हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी शर्तों पर समझौता चाहता है, वहीं ईरान इसे अपनी संप्रभुता और आत्मसम्मान का सवाल मानकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में कूटनीतिक समाधान की संभावनाएं लगातार कमजोर होती जा रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह टकराव आगे बढ़ता है, तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मध्य पूर्व इसकी चपेट में आ सकता है। तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और क्षेत्रीय संघर्षों का विस्तार—ये सभी संभावित परिणाम हैं, जिनसे दुनिया को जूझना पड़ सकता है।

इस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाओं की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यह देखना होगा कि क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस बढ़ते तनाव को कम करने में कोई प्रभावी भूमिका निभा पाता है या फिर यह टकराव एक बड़े सैन्य संघर्ष का रूप ले लेता है।

फिलहाल, हालात बेहद नाजुक हैं और हर गुजरते पल के साथ अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। यह केवल दो देशों के बीच का विवाद नहीं, बल्कि एक ऐसा संकट बनता जा रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति इस टकराव को थाम पाएगी या फिर इतिहास एक नए संघर्ष का गवाह बनने जा रहा है।

16 साल की फरारी खत्म: पहचान बदल-बदलकर भागता रहा चोर आखिर पुलिस के जाल में फंसा

कानून की पकड़ से बचने के लिए इंसान कितनी भी चालाकी क्यों न कर ले, आखिरकार न्याय का पहिया उसे घेर ही लेता है। ऐसा ही एक मामला गुजरात से सामने आया है, जहां Surat पुलिस ने 16 साल से फरार एक शातिर आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी केवल एक अपराधी की पकड़ नहीं, बल्कि पुलिस की धैर्य, रणनीति और लगातार प्रयासों की एक बड़ी सफलता भी मानी जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान Sohanlal Thakarram Bishnoi के रूप में हुई है, जो मूल रूप से Barmer जिले के चंपाबेरी गांव का निवासी है। लगभग 16 साल पहले, वर्ष 2009 में, वह सूरत के महिधरपुरा इलाके में एक टेक्सटाइल एजेंसी में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था। इसी दौरान उसने अपने मालिक Chandumal Tejwani के कार्यालय से नकद और चेक के जरिए करीब 3.60 लाख रुपये की हेराफेरी की और रातोंरात फरार हो गया।

घटना के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और अदालत से वारंट भी जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार पुलिस की पकड़ से बचता रहा। वह कभी एक जगह टिककर नहीं रहा और अपनी

पहचान छुपाने के लिए अलग-अलग राज्यों में भटकता रहा। कभी वह मजदूर बन जाता, तो कभी ड्राइवर का काम करने लगता, ताकि कोई उसे पहचान न सके। यही वजह रही कि इतने लंबे समय तक वह कानून की नजरों से बचा रहा।

इस मामले की जांच लंबे समय से चल रही थी और Surat Police की टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। जोन-5 एलसीबी के अधिकारी Lakhdhir Singh Jhala के नेतृत्व में पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लिया और आरोपी की गतिविधियों पर नजर बनाए रखी।

आखिरकार, सर्विलांस और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पुलिस को एक अहम सुराग मिला। जानकारी मिली कि आरोपी राजस्थान और उत्तर गुजरात के बीच लगातार मूव कर रहा है। हाल ही में सूचना मिली कि वह Mehsana-Palanpur Highway के पास स्थित धरती सती माता होटल के आसपास देखा गया है। यह सूचना पुलिस के लिए निर्णायक साबित हुई।

पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए सादे कपड़ों में होटल के आसपास जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बिना किसी हंगामे के गिरफ्तार कर लिया। इस तरह 16 साल से फरार चल रहा यह शातिर अपराधी आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया।

जांच में यह भी सामने आया कि सोहनलाल ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कई बार नाम और हुलिया बदला। वह छोटे-मोटे काम करके अपनी रोजी-रोटी चलाता रहा और किसी एक जगह पर ज्यादा समय तक नहीं ठहरता था। उसकी यही रणनीति उसे इतने वर्षों तक पुलिस से बचाए रखने में मददगार साबित हुई, लेकिन आखिरकार तकनीकी निगरानी और सतर्क पुलिस टीम के सामने उसकी चालाकी टिक नहीं पाई।

पुलिस का कहना है कि आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए महिधरपुरा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। अब उससे पूछताछ कर यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि फरारी के दौरान उसने और कोई अपराध तो नहीं किया।

यह मामला एक बार फिर यह साबित करता है कि अपराध चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, कानून की पकड़ से बचना संभव नहीं है। समय लग सकता है, लेकिन न्याय अंततः अपना रास्ता खोज ही लेता है। यह गिरफ्तारी न केवल पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, बल्कि समाज के लिए एक स्पष्ट संदेश भी—कि अपराध का अंत निश्चित है, चाहे वह 16 साल बाद ही क्यों न हो।

चुनावी घमासान में छापेमारी से बढ़ा सियासी ताप पवन खेड़ा के घर पहुंची पुलिस पर कांग्रेस का पलटवार

असम विधानसभा चुनाव के बीच सियासी टकराव अब आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर जांच और कार्रवाई के स्तर तक पहुंच गया है। कांग्रेस नेता Pawan Khera और असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma के बीच चल रही जुबानी जंग ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब असम पुलिस ने दिल्ली में पवन खेड़ा के घर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक माहौल और गरमा गया है और कांग्रेस ने इसे लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

दरअसल, विवाद की शुरुआत तब हुई जब पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर कुछ गंभीर आरोप लगाए। इसके जवाब में हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। मामला कानूनी दायरे में आते ही असम पुलिस हरकत में आई और मंगलवार को दिल्ली पहुंचकर खेड़ा के आवास पर जांच की कार्रवाई की। हालांकि, इस कदम को कांग्रेस ने राजनीतिक दबाव और दुरुपयोग करार दिया है।

कांग्रेस नेता Sandeep Dikshit ने इस कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा पेन ड्राइव जब्त किए जाने को लेकर गंभीर आशंका है। उनका आरोप है कि जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, उसमें पारदर्शिता और प्रक्रिया दोनों की कमी नजर आती है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि पेन ड्राइव में क्या सामग्री है, और इस स्थिति में उसके साथ छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

संदीप दीक्षित ने यह भी सवाल उठाया कि जब पहले किसी अन्य मामले में इसी तरह के आरोप लगे थे, तब पुलिस सीधे घर पहुंचने के बजाय एसआईटी का गठन करती है। उन्होंने Gaurav Gogoi के संदर्भ में कहा कि उस समय अलग प्रक्रिया अपनाई गई थी, तो यहां वही मानक क्यों नहीं अपनाए गए। उनके मुताबिक, यह कार्रवाई चयनात्मक और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित प्रतीत होती है।

कांग्रेस का यह भी आरोप है कि छापेमारी के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। दीक्षित के अनुसार, उस समय घर पर कोई जिम्मेदार सदस्य मौजूद नहीं था—सिर्फ गार्ड और घरेलू सहायक थे—इसके बावजूद पुलिस ने दस्तावेज और पेन ड्राइव जब्त कर लिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से न केवल प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं, बल्कि यह भी संदेह पैदा होता है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी या नहीं।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि उनकी पत्नी के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं और विदेशों में संपत्तियां भी हैं। साथ ही एक बड़ी कंपनी से जुड़े आर्थिक पहलुओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों पर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल में इस तरह के घटनाक्रम आमतौर पर सियासी रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं, जहां कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक बयानबाजी एक-दूसरे में घुल-मिल जाती हैं। ऐसे में सच्चाई और आरोपों के बीच अंतर करना आम जनता के लिए मुश्किल हो जाता है।

इस मामले ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या जांच एजेंसियां पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम कर रही हैं या उन पर राजनीतिक प्रभाव हावी हो रहा है। साथ ही, यह सवाल भी उठता है कि क्या चुनावी माहौल में इस तरह की कार्रवाइयों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होती है।

फिलहाल, यह मामला केवल एक एफआईआर या एक छापेमारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़े राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आगे की जांच किस दिशा में जाती है और क्या इन आरोपों और जवाबी आरोपों के बीच सच्चाई सामने आ पाती है या नहीं।

महंगाई की आग में झुलसता पाकिस्तान: पेट्रोल कीमतों ने तोड़ी कमर, सड़कों पर उतरा गुस्सा

पाकिस्तान इस समय एक गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, जहां आम जनता की जिंदगी दिन-ब-दिन मुश्किल होती जा रही है। पेट्रोल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने हालात को इस कदर बिगाड़ दिया है कि अब लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कई जगहों पर प्रदर्शनकारी कफन ओढ़कर विरोध कर रहे हैं, मानो यह संदेश दे रहे हों कि मौजूदा परिस्थितियों में जीना भी किसी संघर्ष से कम नहीं रह गया है।

Pakistan के सिंध प्रांत में व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, जहां Karachi, Hyderabad, Sukkur और Jacobabad जैसे शहरों में नागरिकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मजदूर संगठनों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बढ़ती ईंधन कीमतों और बेकाबू मुद्रास्फीति ने लोगों के धैर्य की सीमा को तोड़ दिया है।

डॉन अखबार के अनुसार, सुक्कुर में Sindh United Party (एसयूपी) ने प्रेस क्लब के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने कफन ओढ़कर प्रतीकात्मक भूख हड़ताल की। यह विरोध न केवल आर्थिक दबाव को दर्शाता है, बल्कि सरकार की नीतियों के प्रति गहरे असंतोष को भी उजागर करता है। पार्टी नेता Eidain Jagirani ने पेट्रोल की कीमतों में कथित 80 पेसो की कटौती को 'भ्रामक' बताया और कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में 137 पेसो प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है।

इसी स्थान पर Pakistan Tehreek-e-Insaf (पीटीआई) के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व Gohar Khan Khoso ने किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़कर 378 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं, जिससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द राहत उपाय नहीं किए गए और करों में कटौती नहीं की गई, तो यह आंदोलन पूरे देश में फैल सकता है।

इस बीच, Awami Tehreek ने भी विरोध की कमान संभाली। तीर चौक से घंटाघर तक निकाली गई विशाल रैली ने यह दिखा दिया कि असंतोष अब केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक जनआंदोलन का रूप लेता जा रहा है। पार्टी नेताओं Noor Ahmed Katyar और Sarwan Jatoi ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह वैश्विक तनावों को बहाना बनाकर ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि कर रही है। उन्होंने हालिया सब्सिडी को भी 'सतही प्रयास' बताते हुए कहा कि इससे जनता के गुस्से को दबाया नहीं जा सकता।

Karachi में भी श्रमिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। National Trade Union Federation (एनटीयूएफ) और Home-Based Women Workers Federation (एचबीडब्ल्यूडब्ल्यूएफ) जैसे संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। इन संगठनों का कहना है कि महंगाई ने मजदूर वर्ग का जीवन असहनीय बना दिया है, जहां रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी करना मुश्किल हो गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का असर केवल परिवहन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। खाद्य पदार्थों से लेकर बिजली और रोजमर्रा की वस्तुओं तक, हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। यही कारण है कि पाकिस्तान में मौजूदा स्थिति केवल ईंधन संकट नहीं, बल्कि एक व्यापक आर्थिक आपात स्थिति बनती जा रही है।

आम नागरिकों का कहना है कि उनकी आय स्थिर है, लेकिन खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। कफन ओढ़कर प्रदर्शन करना इस बात का प्रतीक है कि लोग अब अपनी स्थिति को लेकर बेहद निराश और हताश हो चुके हैं। सरकार की ओर से राहत देने के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि ये प्रयास अपर्याप्त हैं और जमीनी स्तर पर इनका असर नजर नहीं आ रहा। यदि यही स्थिति बनी रही, तो आने वाले दिनों में यह असंतोष और भी उग्र हो सकता है। फिलहाल, पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां आर्थिक संकट और जनाक्रोश मिलकर एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की भूमिका तैयार कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है—क्योंकि अगर हालात पर जल्द काबू नहीं पाया गया, तो यह संकट और भी गहरा सकता है।

संपादकीय

ईरान के खिलाफ अपशब्द हताशा का नतीजा

अमेरिका के इतिहास में शायद ही कोई डोनाल्ड ट्रंप जैसा अधीर, अपरिपक्व बयानवीर और व्यापारी सोच का राष्ट्रपति हुआ हो। संयम व गरिमा शब्द उनके शब्दकोश में ही नहीं हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका-इस्राइल युद्ध के चरम के बीच उन्होंने जिन अपशब्दों का प्रयोग ईरान के लिये किया, वो उनकी हताशा को ही दर्शाता है। उनके बयानों की पूरी दुनिया के साथ अमेरिका के भीतर भी कड़ी आलोचना हुई है। आज अमेरिका के नागरिक भी सोचते होंगे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र में राष्ट्रपति को इतने निरंकुश अधिकार देना क्या प्रजातंत्र के हित में है? निश्चित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर, अपशब्दों और धार्मिक संदर्भों के साथ तेहरान को दी गई चेतावनी, ट्रंप के आवेगपूर्ण उकसावे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एक महाशक्ति के मुखिया द्वारा ऐसी सतही भाषा का प्रयोग न केवल अशोभनीय है बल्कि घातक परिणामों की ओर ले जाने वाला भी है। जाहिरा तौर उनकी धमकियां ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के बजाय, उसे और आक्रामक तरीके से जवाबी कार्रवाई करने को उकसाएंगी। दरअसल,अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह जताने की असफल कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा युद्ध मध्ययुगीन धर्मयुद्ध का विस्तार है। जिसमें सदियों तक ईसाई और मुसलमान आपस में वर्चस्व के लिये युद्ध करते रहे हैं। उन्होंने राजनीति में धार्मिक भावनाओं का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ईरान में मार गिराए गए अमेरिकी फाइटर जहाज के पायलट के बचाव को 'ईस्टर का चमत्कार' बताने से भी गुरेज नहीं किया। जाहिरा तौर पर पुनरुत्थान और आशा का प्रतीक माने जाने वाले ईसाई धर्मावलंबियों के एक पवित्र दिन का हवाला देना, सैन्य अभियान को नैतिक और दैवीय रंग देने का ही एक असफल प्रयास है। निश्चित तौर पर इस तरह की सतही बयानबाजी एक जटिल भू-राजनीतिक संघर्ष को धार्मिकता की एक सरल कहानी में बदलने का जोखिम पैदा करती है। जो ट्रंप की सैन्य अभियान की तार्किकता सिद्ध करने की विफलता को भी दर्शाती है। यही वजह है कि अमेरिकी सांसदों ने यह पता लगाने के लिये जांच की मांग की है कि क्या धार्मिक मान्यताओं का प्रयोग सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने के लिये किया जा सकता है? निश्चित रूप से उन सांसदों की चेतावनी एक मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है, वो है चर्च और राज्य का पृथक्करण का सिद्धांत। उनका तर्क है कि सैन्य निर्णय कानून,रणनीति और जवाबदेही द्वारा निर्देशित होने चाहिए, न कि ईश्वर या बाईबल की भविष्यवाणियों का हवाला देकर। निश्चित रूप से ट्रंप की इन आक्रामक ब्यानबाजियों और कारगुजारियों की कीमत आने वाले वर्षों में अमेरिकियों को चुकानी पड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप की गैरजिम्मेदार धमकियां पश्चिमी एशिया में अमेरिकी रक्षा कर्मियों के जीवन को भी खतरे में डाल सकती हैं। वहीं दूसरी ओर गुप्त राजनयिक प्रयासों को भी पटरी से उतार सकती हैं। दुनिया की महाशक्ति के सबसे शक्तिशाली नेता होने के नाते,उन्हें यह जरूर समझना चाहिए कि उनके बेतुके शब्दों से अमेरिकी विदेशी नीति को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है। जाहिरा तौर पर सशक्त नेतृत्व के लिये जिम्मेदारी के साथ विश्वसनीयता और स्पष्टता भी बेहद जरूरी है। ऐसे में धर्म को हथियार बनाने का उनका यह प्रयास घोर हताशा को ही दर्शाता है। जो इस बात की भी पुष्टि करता है कि अमेरिकी जनता ने एक व्यक्ति की क्षमताओं से कहीं अधिक दायित्व उन्हें सौंपा है। जिसकी वजह यह भी है कि ट्रंप ईरान की क्षमताओं का आकलन करने में चूके हैं। वे जमीनी हकीकत से इतर लगातार अमेरिका की जीत के दावे कर रहे हैं। जब कि वास्तविकता यह है कि सब कुछ खत्म करने के दावों के बावजूद ईरान अमेरिका व इस्राइल को पूरी टक्कर दे रहा है। वह खाड़ी में न केवल अमेरिका के मित्र देशों को निशाना बना रहा है बल्कि इस्राइल के भीतर व मध्यपूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले कर रहा है। ट्रंप के बड़े-बड़े दावों के बावजूद न तो ईरान में सत्ता परिवर्तन ही हुआ है और न ही यह तय हो पाया कि ईरान भविष्य में परमाणु क्षमता हासिल नहीं कर सकता है। उलटे अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आई है।

कच्ची पर्ची व्यवस्था पर रोक से किसानों को मिलेगा न्याय

"हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने कृषि उपज मंडियों के आढ़तियों को अवैध कच्ची पर्ची व्यवस्था तुरंत बंद करने और कानूनन जे-फार्म अनिवार्य रूप से किसानों को देने का आदेश दिया है। यह महत्वपूर्ण कृषि विपणन सुधार है।

भारत में कृषि विपणन का एक व्यवस्थित ढांचा मौजूद था, जो ग्रामीण आत्मनिर्भरता और स्थानीय मंडियों पर आधारित था। किसान न केवल अपने उपभोग के लिए, बल्कि विशेष फसलों जैसे कपास, मसाले, अनाज आदि का उत्पादन व्यापार के लिए भी करते थे। यह विपणन व्यवस्था ग्राम आधारित थी। किसान अपने उत्पादन के साधनों के स्वामी होते थे और स्वतंत्र रूप से अपनी फसल को बाजार में बेचने का निर्णय ले सकते थे।

देश की आज़ादी के बाद, सर छोटूराम द्वारा ब्रिटिश पंजाब में लागू किए गए कृषि उपज मंडी सुधारों के आधार पर कृषि नीति तैयार की गई और राज्यों ने कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम पारित किए, जिसके तहत स्थानीय मंडियां स्थापित की गईं। इसका उद्देश्य बिचौलियों के शोषण को कम करना और किसानों को उचित मूल्य दिलाना था। शुरुआत में, कृषि एवं कृषि प्रबंधन समितियां वास्तव में प्रभावी थीं। इन्होंने कृषि व्यापार में नीलामी आधारित मूल्य निर्धारण, मानकीकृत वजन प्रणाली, लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों और विनियमित लेन-देन प्रक्रियाओं को लागू किया। इनके गठन के समय, एपीएमसी को नीलामी के माध्यम से बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने और किसानों को विपणन की उच्च लागत और उपज के नुकसान से बचाने के लिए एक लोकतांत्रिक समाधान के रूप में सराहा गया था।

समय के साथ, किसानों की सुरक्षा के लिए बनाई गई व्यवस्थाएं ही उनके विरुद्ध कार्य करने लगीं। एक पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली ऐसी प्रणाली में परिवर्तित हो गई जहां कीमतें व्यापारियों और कमीशन एजेंटों द्वारा साज-बाज द्वारा तय की जाने लगी। दशकों से कई संरचनात्मक विकृतियां संचित होती रहीं। भारत की कृषि को जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें कई बिचौलिए शामिल हैं। साथ ही, प्रतिबंधात्मक घरेलू विपणन नीतियां और सीमा संबंधी उपाय भी हैं, जिनके कारण समीक्षाधीन अवधि के अधिकांश समय में कीमतें औसतन अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्तर से नीचे रही हैं। इसके साथ ही, कई वस्तुओं में अंतिम उपभोक्ता मूल्य में किसानों का हिस्सा बेहद कम बना हुआ है।

हालांकि, सीएसीपी ने 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की सिफारिश की थी, लेकिन प्रभावी खरीद मुख्य रूप से एफसीआई के माध्यम से चावल और गेहूं के लिए ही संचालित होती थी, जो धान की कुल बिक्री का केवल एक-चौथाई और गेहूं का 20 प्रतिशत ही एमएसपी पर बेचा गया। दशकों की नीति के बावजूद, अधिकांश किसान गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य प्राप्त नहीं कर सके। दालों या तिलहन की खेती करने वाले किसानों के लिए, एमएसपी अक्सर एक घोषणा मात्र रह जाती थी, जिसके पीछे कोई खरीद तंत्र नहीं होता था। खाद्यान्न जांच समिति की सिफारिशों के बाद, सरकार ने 1950 के दशक के उत्तरार्ध में खाद्यान्नों में सरकारी व्यापार भी शुरू किया। इसके तहत सरकार ने किसानों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं और चावल जैसी प्रमुख वस्तुओं की पूर्व निर्धारित कीमतों पर खरीद की। वर्ष 1961 में पंजाब राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम पारित हुआ, जिसकी नियमावली पंजाब राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम रूल्स-1962 के अन्तर्गत लागू की गई। इस अधिनियम की सेक्शन-43, रूल 24 (11, 12 और 14) के अनुसार आढ़तियों को कृषि उपज बिक्री-तुलाई के तुरंत बाद किसानों को भुगतान और जे-फार्म जारी करना कानूनन अनिवार्य है। लेकिन मंडियों में इन नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए, फसल उपज की सरकारी खरीद में कार्टेल बनाकर और अवैध कच्ची पर्ची (अनौपचारिक रसीद) व्यवस्था द्वारा समर्थन मूल्य से कम पर कृषि उपज खरीदने से किसानों का खुला शोषण हो रहा था। आढ़तियों की अवैध कच्ची पर्ची व्यवस्था से किसानों का आर्थिक नुकसान हो रहा है।

कच्ची पर्ची व्यवस्था से किसानों के लगातार हो रहे शोषण के खिलाफ लेखक द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट ने 27 जनवरी, 2026 को सरकार को अवैध कच्ची पर्ची व्यवस्था पर रोक लगाने के दिशानिर्देश जारी किए। हरियाणा सरकार द्वारा अनुपालना करते हुए 1 अप्रैल को प्रदेश की कृषि उपज मंडियों के आढ़तियों को अवैध कच्ची पर्ची व्यवस्था तुरंत बंद करने और कृषि उपज बिक्री-तुलाई के तुरंत बाद कानूनन जे-फार्म अनिवार्य रूप से किसानों को देने के आदेश जारी किए गए। सरकार द्वारा कच्ची रसीद (पर्ची) व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाने से मंडियों में दस हजार करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक के किसानों के शोषण और सरकारी धन के घोटालों पर भी लगाम लग सकेगी।

प्रेरणा

संकट की घड़ी में निर्णय का साहस

जब प्रकृति अपने उग्र रूप में सामने खड़ी हो जाती है, तब मनुष्य की बुद्धि, धैर्य और साहस की असली परीक्षा होती है। इतिहास के पन्नों में ऐसी अनेक घटनाएं दर्ज हैं, जहां एक सही समय पर लिया गया निर्णय न केवल विनाश को टाल देता है, बल्कि मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन जाता है। कावेरी नदी में आई भयंकर बाढ़ की यह घटना भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें सूझबूझ, नेतृत्व और निडरता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।

कावेरी नदी अपने शांत और जीवनदायिनी स्वरूप के लिए जानी जाती है, लेकिन उस समय उसका रूप विकराल हो चुका था। लगातार हो रही वर्षा के कारण जल स्तर तेजी से बढ़ रहा था। कृष्णराज सागर बांध, जो हजारों लोगों की जीवनरेखा था, अब खतरे के मुहाने पर खड़ा था। यदि जल का स्तर कुछ और बढ़ जाता, तो बांध के टूटने की संभावना थी, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भयंकर तबाही मच सकती थी। खेत, घर, पशु और मानव जीवन—सब कुछ एक पल में नष्ट हो सकता था। ऐसी भयावह स्थिति में विश्व प्रसिद्ध इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के सामने एक बड़ी चुनौती थी। वह केवल एक इंजीनियर ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी और जिम्मेदार नेता भी थे। उन्होंने तुरंत अपने अधीनस्थ इंजीनियरों की एक आपात बैठक बुलाई। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। सभी जानते थे कि समय बहुत कम है और निर्णय अत्यंत कठिन।

बैठक में गहन विचार-विमर्श शुरू हुआ। कई सुझाव आए, कई संभावनाओं पर चर्चा हुई, लेकिन हर समाधान के साथ एक नया जोखिम भी जुड़ा हुआ था। अंततः यह निष्कर्ष निकला कि यदि बांध के सबसे नीचे लगे दरवाजों को खोल दिया जाए, तो अतिरिक्त जल बाहर निकल जाएगा और दबाव कम हो जाएगा। यह उपाय तकनीकी रूप से सही था, लेकिन इसे लागू करना किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता था।

समस्या अब यह थी कि उस खतरनाक स्थिति में जाकर दरवाजे खोले कौन? बांध के नीचे का क्षेत्र पानी से भरा हुआ था, जहां तेज धार के बीच काम करना किसी भी क्षण मौत को आमंत्रण देने जैसा था। बैठक में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी इंजीनियर एक-दूसरे की ओर देखने लगे, मानो कोई इस जिम्मेदारी को उठाने का साहस जुटा ले। यह वह क्षण था, जब ज्ञान और अनुभव से अधिक जरूरत थी साहस और आत्मबल की।

इसी मौन को तोड़ते हुए मैकेनिकल इंजीनियर भालचंद्र पंत केतकर खड़े हुए। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी, आंखों में आत्मविश्वास और आवाज में निश्चय। उन्होंने विश्वेश्वरैया से कहा, "श्रीमान! मुझे आदेश दीजिए, मैं दरवाजे खोल सकता हूं।" यह वाक्य केवल एक प्रस्ताव नहीं था, बल्कि एक संकल्प था—अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण का।

विश्वेश्वरैया के लिए यह क्षण अत्यंत भावुक और कठिन था। एक ओर उनके सामने हजारों लोगों की सुरक्षा का प्रश्न था, तो दूसरी ओर एक कर्मठ इंजीनियर का जीवन। आदेश देना उनके लिए आसान नहीं था। उनके होंठ जैसे थम गए, शब्द गले में अटक गए। यह वह द्वंद्व था, जिसमें एक नेता का हृदय और मस्तिष्क आमने-सामने खड़े होते हैं।

लेकिन केतकर ने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए स्वयं निर्णय लिया और तेजी से दरवाजों की ओर दौड़ पड़े। यह निर्णय केवल साहस का नहीं, बल्कि समय की नाजुकता को समझने की उनकी गहरी सूझबूझ का भी परिचायक था। जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो उसका साहस दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। यही हुआ—केतकर को दौड़ते देख नौ-दस जवान और उनके पीछे-पीछे चल पड़े।

तेज बहाव, गहराई और खतरे के बीच उन्होंने मिलकर काम शुरू किया। हर कदम जोखिम भरा था, लेकिन उनका मनोबल अडिग था। उन्होंने पूरी सावधानी और समझदारी के साथ दरवाजों को खोलना शुरू किया। पानी का वेग धीरे-धीरे नियंत्रित होने लगा। वह दृश्य किसी युद्ध से कम नहीं था—एक ओर प्रकृति की शक्ति और दूसरी ओर मानव का साहस और बुद्धिमत्ता।

कुछ ही समय में स्थिति नियंत्रण में आने लगी। जल का दबाव कम हो गया और बांध सुरक्षित हो गया। एक संभावित आपदा टल गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस पूरे अभियान में सभी लोग सुरक्षित रहे। यह केवल एक तकनीकी सफलता नहीं थी, बल्कि मानवता की जीत थी—साहस, सहयोग और सही समय पर लिए गए निर्णय की जीत। इस घटना से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। सबसे पहली और प्रमुख बात यह है कि संकट के समय घबराने के बजाय शांत रहकर सोचने की आवश्यकता होती है। सही निर्णय वही ले सकता है, जो परिस्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सके और अपने भय पर नियंत्रण रख सके। दूसरी बात यह कि नेतृत्व केवल आदेश देने का नाम नहीं है, बल्कि सही लोगों को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना भी है।

तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि कभी-कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, जब हमें बिना किसी आदेश के, अपने कर्तव्य को समझते हुए स्वयं आगे बढ़ना पड़ता है। केतकर ने यही किया। उन्होंने किसी निर्देश की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि अपने विवेक और साहस के आधार पर निर्णय लिया। यही वास्तविक नायकत्व है।

आज के समय में, जब हम छोटी-छोटी समस्याओं से घबराकर पीछे हट जाते हैं, यह घटना हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर छिपे साहस को पहचानें। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न आए, यदि हमारे पास सही सोच, धैर्य और साहस है, तो हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं।

अंततः यह कहानी केवल एक बांध को बचाने की नहीं है, बल्कि यह उस मानवीय भावना की कहानी है, जो संकट के समय जागृत होती है। यह हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति केवल तकनीक या ज्ञान में नहीं, बल्कि उस साहस में है, जो हमें सही समय पर सही कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है।

Pakistan की गीदड़ भभकी पर West Bengal की सियासत भड़की, चूहे को शेर बताकर किसको डराना चाहती हैं Mamata Banerjee?

भारत के खिलाफ जहर उगलने के आदी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जब कोलकाता को निशाना बनाने की धमकी दी तो यह उनकी बौखलाहट का खुला प्रदर्शन था, लेकिन हैरानी इससे भी ज्यादा इस बात पर है कि भारत के भीतर कुछ नेता इस खोखली धमकी को लेकर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। जिसे बार-बार उसकी हर हरकत पर मुंहतोड़ जवाब मिला हो, जिसे उसकी गुस्ताखियों की सजा उसके घर में घुसकर दी गई हो, उसकी गीदड़ भभकी पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का शोर मचाना न केवल हास्यास्पद है बल्कि चिंताजनक भी है। देखा जाये तो यह एक कमजोर और बेअसर खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने और चूहे को शेर बताकर लोगों में डर पैदा करने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। हम आपको बता दें कि ख्वाजा आसिफ ने पिछले सप्ताह सियालकोट में मीडिया से बातचीत के दौरान यह दावा किया था कि भविष्य में भारत के साथ होने वाला कोई भी संघर्ष सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा और पाकिस्तान कोलकाता जैसे बड़े शहरों को भी निशाना बना सकता है। देखा जाये तो पाकिस्तान की इस ताजा धमकी को भारत में गंभीरता से कम और हास्य के रूप में अधिक लिया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की सैन्य क्षमता, तकनीक और खुफिया तंत्र पाकिस्तान से कहीं अधिक मजबूत है, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी केवल मानसिक दबाव बनाने का असफल प्रयास है।

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प पहलू देश के भीतर की राजनीति बन गई है। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और तीखी भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह तक कह दिया कि उनकी सरकार आने पर दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री से सवाल किया कि उन्होंने इस धमकी पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? दूसरी ओर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तान की किसी भी दुस्साहसिक हरकत का जवाब अभूतपूर्व और निर्णायक होगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगा। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर कहा, "पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उसके बारे में इतना कहूंगा कि उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि 55 साल पहले 1971 में पाकिस्तान ने एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश की थी तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार यदि बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश की तो उसका क्या परिणाम होगा ये भविष्य में पता चल जाएगा।"

अब यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान ने खास तौर पर कोलकाता का नाम क्यों लिया? देखा जाये तो इसके पीछे कई रणनीतिक कारण छिपे हो सकते हैं। एक तो पाकिस्तान यह संदेश देना चाहता है कि वह केवल सीमा क्षेत्रों तक सीमित नहीं है बल्कि भारत के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचने का दावा करता है। कोलकाता जैसे ऐतिहासिक और प्रमुख शहर का नाम लेकर वह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान जानता है चूंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में वहां की राजधानी का नाम लेना तुरंत ही सुर्खियों में ला सकता है।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहले से ही सीमा और घुसपैठ के मुद्दे गर्म रहते हैं। ऐसे में कोलकाता का नाम लेकर पाकिस्तान अप्रत्यक्ष रूप से भारत के आंतरिक राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश करना चाह रहा है। साथ ही, यह एक रणनीतिक भ्रम पैदा करने की चाल भी हो सकती है। जब खतरे को कई दिशाओं में दिखाया जाता है तो विरोधी देश को अपनी सैन्य तैयारी को व्यापक स्तर पर फैलाना पड़ता है। पाकिस्तान संभवतः भारत की रणनीतिक एकाग्रता को बांटने की कोशिश कर रहा है।

इसके अलावा, पाकिस्तान के घरेलू हालात भी इस बयानबाजी के पीछे एक बड़ा कारण हैं। आर्थिक संकट, आंतरिक अस्थिरता और पश्चिमी सीमाओं पर तनाव के बीच वहां की सरकार भारत विरोधी बयान देकर अपने नागरिकों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित जैसे लोगों के बयान भी इसी मानसिकता को दर्शाते हैं, जिनमें भारत के बड़े शहरों को निशाना बनाने की बात कही गई है। यह सब मिलकर एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा प्रतीत होता है।

देखा जाये तो यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान की यह धमकी उसकी कमजोरी और हताशा का प्रतीक है। भारत आज न केवल सैन्य बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक रूप से भी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में इस तरह की गीदड़ भभकियां केवल शोर से अधिक कुछ नहीं हैं। भारत की नीति स्पष्ट है कि किसी भी आक्रामकता का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। और इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान ने सीमा लांघने की कोशिश की है, उसे मुंहतोड़ जवाब मिला है।

अभियान

आस्था, पहचान और परंपरा के बीच खड़ा एक नया सवाल

उत्तराखंड की हिमालयी वादियों में स्थित चार धाम केवल धार्मिक स्थल नहीं हैं, बल्कि वे करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक पहचान के केंद्र हैं। हर वर्ष जब यात्रा का समय आता है, तो देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु इन पवित्र धामों की ओर रुख करते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ—ये चारों धाम न केवल सनातन परंपरा की धरोहर हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा को भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। लेकिन हाल ही में गंगोत्री धाम और मुखबा में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक को लेकर जो निर्णय सामने आया है, उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

यह मुद्दा केवल एक नियम या प्रशासनिक फैसले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आस्था, परंपरा, संविधान और सामाजिक समरसता जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छूता है। गंगोत्री धाम से जुड़े ट्रस्ट का कहना है कि यह निर्णय मंदिर की पवित्रता और सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए लिया गया है। उनके अनुसार, इन स्थानों को केवल पर्यटन स्थल के रूप में देखना उचित नहीं है, बल्कि इन्हें एक जीवंत धार्मिक केंद्र के रूप में समझना चाहिए, जहां हर क्रिया और आचरण एक निश्चित धार्मिक मर्यादा के अंतर्गत होता है।

यह तर्क अपने आप में एक गहरी सोच को दर्शाता है। भारत में मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं होते, बल्कि वे एक विशेष जीवन पद्धति और सांस्कृतिक अनुशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। गंगोत्री जैसे स्थान, जहां गंगा नदी का उद्गम माना जाता है, वहां की धार्मिक संवेदनाएं और भी अधिक गहरी होती हैं। ऐसे में ट्रस्ट द्वारा लिया गया यह निर्णय उनके दृष्टिकोण से परंपरा की रक्षा का एक प्रयास माना जा सकता है।

लेकिन दूसरी ओर, यह निर्णय कई सवाल भी खड़े करता है। क्या किसी धार्मिक स्थल पर किसी विशेष समुदाय के लोगों के प्रवेश पर रोक लगाना आज के लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे में उचित है? भारत एक ऐसा देश है जहां "वसुधैव कुटुंबकम्" की भावना को सर्वोपरि माना जाता है। यहां विविधता में एकता केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। ऐसे में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध इस दर्शन के साथ टकराव पैदा करता है।

इस पूरे मुद्दे का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। चार धामों का प्रबंधन देखने वाली समिति ने केवल सुझाव के स्तर पर इस विषय को रखा है। इसका मतलब यह है कि यह अभी विचाराधीन है और इस पर अंतिम निर्णय लेना बाकी है। ऐसे में यह कहना कि यह नियम अन्य धामों—जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री—में भी लागू हो जाएगा, फिलहाल जल्दबाजी होगी।

फिर भी, यह चर्चा अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा और आधुनिक समाज की समावेशिता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। एक ओर जहां मंदिरों की अपनी परंपराएं और नियम होते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज का बदलता स्वरूप और वैश्विक दृष्टिकोण भी एक सच्चाई है।

चार धाम यात्रा केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा आधार है। हर साल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें दुकानदार, होटल संचालक, गाइड, मजदूर और अन्य सेवाकर्मी शामिल होते हैं, जो विभिन्न समुदायों से आते हैं। यदि प्रवेश पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है, तो इसका प्रभाव इन लोगों की आजीविका पर भी पड़ सकता है।

इसके अलावा, यह भी ध्यान देने योग्य है कि चार धाम यात्रा में केवल भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। कई विदेशी पर्यटक भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को समझने के लिए इन स्थलों की यात्रा करते हैं। ऐसे में यदि उनके प्रवेश पर रोक लगाई जाती है, तो यह भारत की उस छवि को भी प्रभावित कर सकता है, जो उसे एक खुले और समावेशी समाज के रूप में प्रस्तुत करती है।

हालांकि, यह भी सच है कि कई धार्मिक स्थलों पर पहले से ही कुछ नियम लागू हैं। जैसे कि कुछ मंदिरों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति होती है, या फिर कुछ विशेष आचार-व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होता है। इन नियमों को वहां की परंपराओं और मान्यताओं के आधार पर स्वीकार किया जाता है। लेकिन अंतर यह है कि ऐसे नियम लंबे समय से चले आ रहे होते हैं, जबकि गंगोत्री में लिया गया यह निर्णय अपेक्षाकृत नया है, इसलिए इस पर चर्चा होना स्वाभाविक है।

इस पूरे मुद्दे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाए। केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक पहलुओं को भी समझा जाए। संवाद और सहमति के बिना लिया गया कोई भी निर्णय लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता। यह भी जरूरी है कि इस विषय को राजनीतिक या भावनात्मक रूप से भड़काने के बजाय संतुलित और समझदारी से देखा जाए। आस्था एक व्यक्तिगत और गहरी भावना होती है, और इसका सम्मान करना हर किसी की जिम्मेदारी है। वहीं, समाज में समरसता बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि गंगोत्री में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक का मुद्दा केवल एक शुरुआत हो सकता है, लेकिन यह किस दिशा में जाएगा, यह पूरी तरह से आने वाले समय और लिए जाने वाले निर्णयों पर निर्भर करेगा। यह एक ऐसा विषय है, जिसमें जल्दबाजी से अधिक समझदारी और संवाद की आवश्यकता है।

भारत की ताकत उसकी विविधता में है। यहां अलग-अलग धर्म, संस्कृति और परंपराएं एक साथ मिलकर एक सुंदर तस्वीर बनाती हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि हम किसी भी निर्णय को इस व्यापक दृष्टिकोण के साथ देखें, ताकि आस्था भी बनी रहे और समाज की एकता भी अक्षुण्ण रहे।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

अहमदाबाद में रेडी-टू-ईट डोसा ने छीनी दो मासूम बहनों की जान, पिता अस्पताल में भर्ती, डेयरी मालिक ने दी सफाई

अहमदाबाद। गुजरात की व्यस्त गलियों और रंग-बिरंगे बाजारों में रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुके रेडी-टू-ईट खाद्य पदार्थों की विश्वसनीयता पर अब गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। चांदखेड़ा इलाके में स्थित एक सामान्य परिवार की खुशियों को महज एक पैकेट डोसा बैटर ने उजाड़ दिया, जिससे दो मासूम बहनों की मौत हो गई और पिता की हालत गंभीर बनी। यह घटना पूरे इलाके में मातम और दहशत फैलाने वाली साबित हुई और शहर के नागरिकों को अपने खाद्य सुरक्षा मानकों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया।

घटना 1 अप्रैल, 2026 की है, जब परिवार ने अपने नाश्ते के लिए चांदखेड़ा की जानी-मानी 'घनश्याम डेयरी' से रेडी-टू-ईट डोसा बैटर खरीदा। शुरुआत में परिवार को यह सामान्य उपभोग का हिस्सा लगा, लेकिन जल्द ही स्थिति भयावह हो गई। सबसे पहले पिता ने डोसा खाया और उसकी सेहत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस समय परिवार को यह अंदाजा नहीं था कि उनकी सेहत पर हमला करने वाला यही डोसा बैटर है।

अगले दिन मां और उनकी साढ़े तीन साल की बड़ी बेटी ने भी वही बैटर से बना डोसा खाया। छोटी बच्ची, जो महज तीन महीने की थी, अभी मां के दूध पर निर्भर थी, परंतु संक्रमण का असर उस तक भी पहुँच गया। परिणामस्वरूप, छोटी बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि बड़ी बहन की भी अगले ही दिन मौत हो गई। इस भयावह घटना ने पूरे परिवार के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।

घटना की खबर फैलते ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। अहमदाबाद नगर निगम और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की टीम ने 'घनश्याम डेयरी' का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध खाद्य सामग्री, बैटर और अचार के नमूने लिए। प्रशासन ने कहा कि यह जांच बेहद गंभीर है और इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि मासूमों की मौत वास्तव में फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई या बैटर को संरक्षित करने और संभालने में कोई चूक हुई।

डेयरी के प्रबंधक ने अपने पक्ष में सफाई दी और कहा कि 'हम रोजाना 100 किलो से अधिक बैटर बेचते हैं और केवल इसी एक परिवार के साथ यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। हमारे पास वॉयस रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं, और अन्य ग्राहकों से हमने फीडबैक लिया है, जिसमें कोई शिकायत सामने नहीं आई।' उनका कहना था कि सभी उत्पादन और वितरण प्रक्रियाएँ मानक के अनुसार होती हैं और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, न कि प्रणालीगत लापरवाही।

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि रेडी-टू-ईट खाद्य पदार्थों में उचित तापमान पर संग्रहण और वितरण न होना, छोटी सी लापरवाही भी भारी नुकसान कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों और शिशुओं में प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण ऐसे उत्पादों का सेवन खतरनाक हो सकता है। इस मामले में परिवार और पूरे इलाके के लिए यह एक कड़ा चेतावनी संदेश है कि बाजार से खरीदे गए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए।

अहमदाबाद की इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया। स्थानीय निवासी और पड़ोसी घटना के बाद भावनात्मक रूप से प्रभावित हुए और माता-पिता ने अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। कई परिवारों ने फोरेंसिक रिपोर्ट आने तक रेडी-टू-ईट उत्पादों का सेवन रोक दिया। इस हादसे ने खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की और यह संदेश दिया कि बाजार में बिकने वाले हर पैकेट की जांच, ताजगी और संरक्षा सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है।

पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की जांच अभी जारी है और FSL की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि बैटर में कोई विषाक्त पदार्थ था या फिर बैक्टीरिया और संक्रमण की वजह से बच्चों की मौत हुई। प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि यदि कोई अन्य उपभोक्ता इसी प्रकार की समस्या का सामना करता है तो तुरंत शिकायत दर्ज कराई जाए।

इस घटना ने न केवल परिवार की खुशियों को छीन लिया, बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि खाद्य सुरक्षा और जिम्मेदारी केवल उत्पादक की नहीं, बल्कि उपभोक्ता की भी है। विशेषज्ञों का कहना है कि हर उपभोक्ता को उत्पाद का उत्पादन और समाप्ति तिथि, पैकिंग और संग्रहण की जानकारी जाननी चाहिए। साथ ही, बच्चों और शिशुओं को रेडी-टू-ईट खाद्य पदार्थ देते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सभी डेयरियों और खाद्य उत्पाद विक्रेताओं को अलर्ट जारी किया है कि वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस भयानक हादसे ने शहरवासियों को यह सोचने पर मजबूर किया कि एक छोटी सी लापरवाही कैसे दो मासूम जिंदगियों को निगल सकती है।

इस दुखद कहानी ने हर माता-पिता को सावधान कर दिया है कि बच्चों के लिए केवल स्वस्थ्य, सुरक्षित और विश्वसनीय खाद्य पदार्थ ही उपयुक्त हैं। चांदखेड़ा की यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि भोजन केवल पोषण नहीं, बल्कि जीवन और सुरक्षा का मुद्दा भी है।

वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा प्रतापनगर - एकतानगर रेलखंड का निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 2026 को प्रतापनगर - एकतानगर रेलखंड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान श्री भडके ने मोरिया स्टेशन को डी क्लास से बी क्लास में बदलने के लिए किये जा रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य का संरक्षा निरीक्षण भी किया।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना जी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 2026 को प्रतापनगर - एकतानगर रेलखंड का निरीक्षण किया गया। कुंढ़ेला तथा तिलकवाडा स्टेशन पर उन्होंने निर्माणधीन फुट ओवर ब्रिज, स्टेशन मास्टर पैनल रूम तथा हाई लेवल प्लेटफॉर्म नं.1 का निरीक्षण किया। डभोई स्टेशन पर उन्होंने निर्माणधीन फुट ओवर ब्रिज व रेलवे प्लेटफॉर्मो का निरीक्षण किया तथा संबंधित विभाग को कार्यों को समय पर पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए। तिलकवाडा स्टेशन पर उन्होंने निर्माणाधीन ओवर ब्रिज का कार्य तेज गति से करने तथा यात्री सुविधाओं को ध्यान में रख कर कार्य करने का निर्देश दिया। मंडल प्रबंधक जी ने इन सभी स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा हेतु पानी, शेडकवर, सफाई, लाइट, पंखे, यात्रियों के बैठने हेतु सीटों आदि का निरीक्षण किया तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी स्टेशनों पर सफाई हेतु विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए।

श्री भडके ने मोरिया स्टेशन को डी क्लास से बी क्लास में बदलने के लिए किये जा रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य का संरक्षा निरीक्षण भी किया और सभी रेलकर्मियों को सुरक्षित व संरक्षित तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। मोरिया स्टेशन पर उन्होंने सिग्नल व प्वाइंट इंटरलॉकिंग का निरीक्षण किया। मोरिया स्टेशन के बी क्लास में परिवर्तित होने से प्रतापनगर - एकतानगर रेलखंड में सेक्शन कैपेसिटी में वृद्धि होगी, जिससे इस रेलखंड में अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन संभव होगा।

वाल्मीकि समुदाय में घरेलू विवादों के समाधान के लिए कल्याण समिति का गठन किया गया, सुलह के प्रयास शुरू किए गए

(छगन लाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत. दक्षिण गुजरात के वाल्मीकि समुदाय के नेताओं की एक बैठक 7 अप्रैल 2026 को शाम 5:00 बजे सूरत ओपेरा हाउस में वरिष्ठ अधिवक्ता और उद्योगपति श्री डी.सी. सोलंकी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें वाल्मीकि समुदाय की समस्याओं पर चर्चा की गई। वाल्मीकि समुदाय में विवाह के बाद घरेलू विवादों की दर बढ़ रही है और सामान्य मामलों में भी अदालती कार्यवाही करनी पड़ती है। विवाद वर्षों तक अनसुलझे रहते हैं। एक ओर तो यह समुदाय आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर यदि कोई मामला अदालत में जाता है तो दोनों पक्षों को लंबे समय तक कष्ट सहना पड़ता है और भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। पति-पत्नी दोनों को लंबे समय तक मानसिक पीड़ा भी सहनी पड़ती है। कुछ मामले तो पारिवारिक अदालतों में वर्षों से लंबित हैं। ऐसी स्थिति के समाधान के लिए वाल्मीकि समुदाय कल्याण समिति का गठन किया गया है। इस समिति की पहली बैठक जल्द ही नवसारी में आयोजित की जाएगी, जिसमें अहवा, वलसाड और नवसारी के पक्षों को आमंत्रित किया जाएगा और सुलह कराने के प्रयास किए जाएंगे। इस समिति के पदाधिकारियों की नियुक्ति निम्नानुसार की गई है।

अध्यक्ष श्री डी.सी. सोलंकी एडवोकेट

उपाध्यक्ष श्री बिपिनभाई राठौड़ एडवोकेट

उपाध्यक्ष श्री भाई लाल बी. वैष्णव सामाजिक कार्यकर्ता

महासचिव श्री मयंकभाई जे. सोलंकी एडवोकेट

मंत्री श्री कांतिलाल बी. सोलंकी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं समिति सदस्य श्री महेंद्रभाई सोलंकी एडवोकेट, श्री अश्विनभाई वैष्णव एडवोकेट, श्री जीतूकुमार शाह एडवोकेट, श्री शशिकांत सोलंकी, श्री कानूलाल सोलंकी, श्री रविभाई सुरती, श्री श्यामभाई तेनिया आदि का चयन किया गया है।

आस्था और अंधविश्वास के बीच की रेखा: नासिक के भोंडुबाबा की कहानी से एक चेतावनी और जागरूकता संदेश

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। आस्था और अंधविश्वास के बीच एक पतली सी रेखा होती है। और यही कारण है कि आस्था रखने वाले भी अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं। कहते हैं कि आस्था को प्रमाण चाहिए। लेकिन अब कलियुग में, अगर हम आस्था की बात करें तो लोग संदेह पैदा कर देते हैं और पूछते हैं कि क्या यह है भी? क्या यह सच में हो रहा है? इसीलिए कहा जाता है कि आस्था को प्रमाण चाहिए, अंधविश्वास को नहीं? इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र के नासिक के अशोक खरात हैं। फिर भी, अंधविश्वास एक ऐसी बीमारी है जो ठीक हो सकती है, लेकिन महामारी का रूप ले चुकी है। जब किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता से ज्यादा किसी चमत्कार पर भरोसा होता है, तो वह अंधविश्वास के रास्ते पर चल पड़ता है। और यह विनाश की ओर ले जाता है। हवा चलती है, हम उसे महसूस करते हैं, हम उसे देखते नहीं, फिर भी हम मानते हैं कि हवा एक प्राकृतिक चमत्कार है। इसे प्रमाण की जरूरत नहीं है।

हम प्रकृति या किसी विशेष धार्मिक या सांप्रदायिक विश्वास के अनुसार, कुछ अलौकिक शक्तियों को, जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, अलग-अलग नाम दे देते हैं। व्यक्तिगत विश्वास के अनुसार, व्यक्ति उनमें आस्था या विश्वास रख सकता है। चूंकि आस्था एक अत्यंत व्यक्तिगत मामला है, इसलिए इस पर किसी और को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। सवाल तब उठता है जब कोई अंधविश्वासी व्यक्ति इन दोनों के बीच आकर प्रकृति का अवतार होने का ढोंग करता है और उससे कुछ लाभ उठाता है। उस समय, व्यक्ति की आस्था अंधविश्वास में बदल जाती है।

और इसमें, अशोक खरात की तरह भोंदू बाबा ने ऐसे धोखेबाजों के लिए मराठी भाषा में 'भोंदूबाबा' शब्द का इस्तेमाल किया है। महाराष्ट्र के इस नए भोंदू बाबा का नाम प्रकाशित हुआ, जिससे महाराष्ट्र में हलचल मच गई और अब जब बाबा जेल में हैं और एसआईटी की जांच में सच्चाई सामने आ रही है, तो भालभल के वैवाहिक जीवन में भी उथल-पुथल मच जाए तो आश्चर्य नहीं होगा।

NHSRCL परियोजना कार्य के चलते अहमदाबाद मंडल की ट्रेनें प्रभावित

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) परियोजना के अंतर्गत गेरतपुर–अहमदाबाद रेलखंड पर प्रीकास्ट पोर्टल बीम स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य के लिए दिनांक 08 अप्रैल, 2026 (बुधवार) को ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। जिसके कारण अहमदाबाद मंडल से संबंधित निम्नलिखित ट्रेनें प्रभावित रहेंगीः

निरस्त ट्रेनें

- ट्रेन संख्या 69102 वटवा–वडोदरा मेमू, दिनांक 08.04.2026 को निरस्त रहेगी।
- ट्रेन संख्या 69115 वडोदरा–वटवा मेमू, दिनांक 08.04.2026 को निरस्त रहेगी।

आंशिक रूप से निरस्त ट्रेन

- ट्रेन संख्या 19033 वलसाड–अहमदाबाद गुजरात क्वीन, दिनांक 08.04.2026 को वडोदरा–अहमदाबाद के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

पुनर्निर्धारित (री-शेड्यूल) ट्रेन

- ट्रेन संख्या 12009 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस, दिनांक 08.04.2026 को मुंबई सेंट्रल से अपने निर्धारित समय से लगभग 1 घंटा 15 मिनट देरी से प्रस्थान करेगी।

विनियमित (रेगुलेट) ट्रेनें

- ट्रेन संख्या 19484 सहरसा–अहमदाबाद एक्सप्रेस, दिनांक 08.04.2026 को वडोदरा मंडल में लगभग 2 घंटे 10 मिनट विनियमित की जाएगी।
- ट्रेन संख्या 12834 हावड़ा–अहमदाबाद एक्सप्रेस, दिनांक 08.04.2026 को वडोदरा मंडल में लगभग 2 घंटे 10 मिनट विनियमित की जाएगी।

ट्रेनो के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

चलती ट्रेन में चढ़ते समय गिरते यात्री की जान बचाई RPF जवानों की सतर्कता से टली बड़ी दुर्घटना

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर दिनांक 06 अप्रैल, 2026 को रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों की तत्परता एवं साहस से एक यात्री की जान बचाई गई।

- प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रातः लगभग 04:00 बजे ट्रेन संख्या 09009 के प्रस्थान के समय एक यात्री जनरल कोच में चढ़ते हुए प्लेटफॉर्म एवं ट्रेन के बीच बने गैप में गिरने लगा। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर तैनात हेड कांस्टेबल किशोरी लाल बलाई ने तत्काल उसे बचाने का प्रयास किया, किन्तु ट्रेन की गति तेज होने के कारण यात्री उनकी पकड़ में नहीं आ सका।
- उसी समय मौके पर उपस्थित RPF की CPDS (Crime Prevention and Detection Squad) टीम के सहायक उप निरीक्षक रमन कुमार एवं कॉन्स्टेबल छोटू लाल, जो सादी वर्दी में ड्यूटी पर थे, ने अदम्य साहस एवं तत्परता का परिचय देते हुए तुरंत दौड़कर बिना अपनी जान की परवाह किए उक्त यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

- बाद में यात्री से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम महेंद्र (उम्र 42 वर्ष), निवासी सूरत (गुजरात) बताया तथा यह भी बताया कि वह अपने परिवार के साथ सूरत से गांधीधाम तक की यात्रा कर रहा था और अहमदाबाद स्टेशन पर चाय-नाश्ता लेने हेतु उतरा था। यात्री ने स्वयं को पूर्णतः सुरक्षित एवं बिना किसी चोट के बताया।
- अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने बताया कि ऐसे कर्तव्यनिष्ठ एवं सतर्क कर्मचारी रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- यह घटना RPF के जवानों की सतर्कता, कर्तव्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट सेवा भावना का प्रतीक है। दोनों जवानों द्वारा किया गया यह कार्य अत्यंत सराहनीय है तथा उन्होंने समय रहते एक अमूल्य जीवन को बचाकर मानवता की मिसाल प्रस्तुत की है।

बुलेट ट्रेन परियोजना कार्य के कारण अहमदाबाद मंडल से गुजरने वाली 04 ट्रेनें प्रभावित

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) की बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत गेरतपुर–अहमदाबाद रेलखंड पर प्रीकास्ट पोर्टल बीम स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य के लिए दिनांक 08 अप्रैल, 2026 को ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा।

इस ट्रैफिक ब्लॉक के चलते अहमदाबाद मंडल से गुजरने वाली निम्नलिखित ट्रेनें प्रभावित रहेंगीः

रद्द ट्रेनें:

1.ट्रेन संख्या 22959 वडोदरा–जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो अहमदाबाद मंडल के अहमदाबाद, साबरमती, चांदलोड़िया, आंबली रोड एवं वीरमगाम स्टेशनों से होकर चलती है, दिनांक 08.04.2026 को रद्द रहेगी।

2.ट्रेन संख्या 22960 जामनगर–वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो अहमदाबाद मंडल के वीरमगाम, आंबली रोड, चांदलोड़िया, साबरमती एवं अहमदाबाद स्टेशनों से होकर चलती है, दिनांक 09.04.2026 को रद्द रहेगी।

मार्ग में रेगुलेट होने वाली ट्रेनें:

1.ट्रेन संख्या 22718 सिकंदराबाद–राजकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो अहमदाबाद मंडल के मणिनगर, अहमदाबाद एवं वीरमगाम स्टेशनों से होकर चलती है, दिनांक 08.04.2026 को वडोदरा मंडल में लगभग 01 घंटे के लिए रेगुलेट की जाएगी।

2.ट्रेन संख्या 15636 गुवाहाटी–ओखा एक्सप्रेस, जो अहमदाबाद मंडल के अहमदाबाद एवं वीरमगाम स्टेशनों से होकर चलती है, दिनांक 08.04.2026 को वडोदरा मंडल में लगभग 01 घंटे के लिए रेगुलेट की जाएगी।

कॉटन वायदा में 820 रुपये का ऊछाल: सोना वायदा 151 रुपये और चांदी वायदा 1623 रुपये लुढ़का: क्रूड 142 रुपये तेज

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 128871.13 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 29176.08 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 99694.41 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 35792 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3254.12 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 17864.66 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 149759 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 150860 रुपये और नीचे में 149201 रुपये पर पहुंचकर, 149981 रुपये के पिछले बंद के सामने 151 रुपये या 0.1 फीसदी औंधकर 149830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा 258 रुपये या 0.22 फीसदी की तेजी के संग 119755 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 53 रुपये या 0.35 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 14992 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी मई वायदा सत्र के आरंभ में 148384 रुपये के भाव पर खूलकर, 149394 रुपये के दिन के उच्च और 147738 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 73 रुपये या 0.05 फीसदी लुढ़ककर 148341 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम 148800 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 149699 रुपये और नीचे में 148127 रुपये पर पहुंचकर, 148854 रुपये के पिछले बंद के सामने 102 रुपये या 0.07 फीसदी औंधकर 148752 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सत्र के आरंभ में 232000 रुपये के भाव पर खूलकर, 235547 रुपये के दिन के उच्च और 230970 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 233379 रुपये के पिछले बंद के सामने 1623 रुपये या 0.7 फीसदी गिरकर 231756 रुपये प्रति किलो हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 1468 रुपये या 0.62 फीसदी लुढ़ककर 234630 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 1352 रुपये या 0.57 फीसदी गिरकर 234830 रुपये प्रति किलो हुआ।

मेटल वर्ग में 1944.19 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 2.75 रुपये या 0.24 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1164.25 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 5.7 रुपये या 1.76 फीसदी की बढ़त के साथ 330.15 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 4.6 रुपये या 1.31 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 357 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 75 पैसे या 0.38 फीसदी की नरमी के साथ 195.5 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कमोडिटी वायदाओं में 29176.08 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 99694.41 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 17864.66 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 35792 पॉइंट के स्तर पर

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 9311.68 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा 10722 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 10888 रुपये और नीचे में 10386 रुपये पर पहुंचकर, 142 रुपये या 1.34 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 10730 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 145 रुपये या 1.37 फीसदी बढ़कर 10730 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 263.6 रुपये के भाव पर खूलकर, 268.6 रुपये के दिन के उच्च और 260.3 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 265.8 रुपये के पिछले बंद के सामने 2.5 रुपये या 0.94 फीसदी की तेजी के संग 268.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा 2.5 रुपये या 0.94 फीसदी की मजबूती के साथ 268.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा 1050.8 रुपये पर खूलकर, 1.3 रुपये या 0.12 फीसदी बढ़कर 1052 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। कॉटन अप्रैल वायदा 28500 रुपये के भाव पर खूलकर, ऊपर में 28990 रुपये और नीचे में 28500 रुपये के स्तर को छूकर, 820 रुपये या 2.91 फीसदी के ऊछाल के साथ 28990 रुपये प्रति गांठ ट्रेड हो रहा था। इलायची का अप्रैल वायदा प्रति किलो 31 रुपये या 1.21 फीसदी के सुधार के साथ 2600 रुपये हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 12054.85 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 5809.81 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1000.85 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 420.30 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 39.93 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 476.14 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 7419.14 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1852.70 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 2.53 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन के वायदाओं में 1.00 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 8100 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 47089 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 26370 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 381930 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 53430 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7133 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 20158 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 78945 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 22657 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 42442 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 35687 पॉइंट पर खूलकर, 35819 के उच्च और 35687 के नीचले स्तर को छूकर, 188 पॉइंट घटकर 35792 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल अप्रैल 14000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 19.3 रुपये की बढ़त के साथ 135.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 70 पैसे के सुधार के साथ 12.6 रुपये हुआ। सोना अप्रैल 170000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 13 रुपये की गिरावट के साथ 481.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 67.5 रुपये की गिरावट के साथ 703 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5 पैसे के सुधार के साथ 14.61 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 330 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.66 रुपये की बढ़त के साथ 6.5 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल अप्रैल 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 19 रुपये की गिरावट के साथ 566.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 75 पैसे की नरमी के साथ 9.75 रुपये हुआ। सोना अप्रैल 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 64.5 रुपये की गिरावट के साथ 2056.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 47 रुपये की गिरावट के साथ 344.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 11 पैसे की नरमी के साथ 8.9 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 325 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.02 रुपये की गिरावट के साथ 4.6 रुपये हुआ।

बीकानेर में 10 फीट लंबी सुरंग का खुलासा, हेडफोन और बिजली के तार बरामद, सुरक्षा एजेंसियों में हाई अलर्ट

बीकानेर। राजस्थान के सीमावर्ती जिले बीकानेर में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी का मामला सामने आया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। सादुल गंज इलाके में मिलिट्री प्रतिष्ठान के बेहद करीब जमीन के नीचे एक संदिग्ध सुरंग मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और प्रशासन को तत्काल हाई अलर्ट जारी करना पड़ा। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह सिर्फ एक साधारण सुरंग नहीं थी, बल्कि इसमें उच्च तकनीकी निगरानी उपकरण, संचार यंत्र और बिजली के तार लगे हुए थे, जो इसे एक संगठित और योजना बद्ध जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बनाते हैं।

सूत्रों के अनुसार, सादुल गंज इलाके में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की खुफिया सूचना मिलने के बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस (MI) की टीम ने गहन निरीक्षण किया। डूंगर कॉलेज के पीछे स्थित रेतीले भूखंड में जब जमीन खोदी गई, तो लगभग दस फीट लंबी सुरंगनुमा संरचना मिली। सुरंग के भीतर से संचार सुनने वाले हेडफोन, बिजली के तार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि इन उपकरणों का इस्तेमाल सैन्य सिग्नल पकड़ने, गुप्त निगरानी करने और सूचना इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा था।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि सुरंग के भीतर 23 मार्च के समाचार पत्र में लिपटी चार रोटियां भी मिलीं। इससे स्पष्ट होता है कि सुरंग में कुछ समय तक कोई मौजूद था और सुरक्षा एजेंसियों की दबिश से कुछ समय पहले ही इसे छोड़ा गया। यह तथ्य सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि यह संकेत देता है कि दुश्मन तत्व यहां लगातार निगरानी कर रहे थे और किसी भी संवेदनशील गतिविधि के लिए तैयार थे।

स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता ने समय रहते इस खतरे को बेनकाब किया। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इसे मल्टी-एजेंसी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में रखा गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), सीआईडी, मिलिट्री इंटेलिजेंस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। सुरंग से बरामद सभी उपकरणों की तकनीकी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन उपकरणों द्वारा जुटाई गई सूचना कहां भेजी जा रही थी और किसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था।

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब दुश्मन तत्व पारंपरिक घुसपैठ और सीमा पार करने के पुराने तरीकों के बजाय अंडरग्राउंड रास्तों का इस्तेमाल कर रहे

हैं। यह रणनीति सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के लिए नई चुनौती पेश करती है। बीकानेर जैसे सैन्य और सीमावर्ती शहरों में ऐसी गतिविधियों का खुलासा पहले भी हुआ है, लेकिन आधुनिक निगरानी उपकरणों और तकनीकी सहायता के साथ बनाई गई यह सुरंग पहली बार सामने आई है। स्थानीय लोग और व्यापारी इस घटना से भयभीत हैं। कई लोगों ने सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता की सराहना की, जबकि कुछ ने चिंता जताई कि यदि समय पर जांच न की जाती, तो यह किसी बड़े आतंकवादी या जासूसी नेटवर्क की बड़ी साजिश का हिस्सा बन सकता था। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें और किसी भी असामान्य घटना की तुरंत सूचना दें। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की अंडरग्राउंड सुरंगों का निर्माण और उनमें तकनीकी उपकरणों की मौजूदगी किसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश या जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। सुरंग की खोज ने यह स्पष्ट कर दिया कि दुश्मन लगातार अपनी रणनीति बदल रहा है और अब अधिक चुपके से और गुप्त तरीके से सैन्य प्रतिष्ठानों और संवेदनशील इलाकों की निगरानी कर रहा है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने सुरंग से कई साक्ष्य जुटाए हैं। बरामद उपकरणों में संचार सुनने वाले हेडफोन, बिजली के तार, वायरिंग सिस्टम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्र शामिल हैं। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि इन उपकरणों के जरिए दुश्मन तत्व सैन्य संचार और रणनीतिक गतिविधियों की जानकारी ले सकते थे। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अभी इस मामले की जांच जारी है और जल्द ही सुरंग के निर्माण और उसमें पाए गए उपकरणों से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।

बीकानेर जिले में सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके में अतिरिक्त गश्त बढ़ा दी है। सड़क पर और सैन्य प्रतिष्ठानों के आसपास निगरानी तेज कर दी गई है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि को तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करें। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सीमावर्ती इलाकों में इस तरह की सुरंगों की संभावना पहले भी रहती थी, लेकिन तकनीकी उपकरणों से लैस सुरंग का खुलासा यह दिखाता है कि दुश्मन अपनी जासूसी रणनीति को लगातार विकसित कर रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन निगरानी, तकनीकी उपकरणों की मदद से पैट्रोलिंग और स्थानीय सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता है।

मल्टी-एजेंसी इन्वेस्टिगेशन टीम अब सुरंग के आसपास के इलाके, जमीन के नीचे संभावित अन्य मार्ग और सुरक्षा उपकरणों के संचालन की जांच कर रही है। टीम का दावा है कि जल्द ही सुरंग के निर्माण और इसमें पाए गए उपकरणों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली जाएगी। सुरंग के भीतर 23 मार्च के समाचार पत्र में लिपटी रोटियों के मिलने से यह संकेत मिलता है कि इसमें लगातार कोई सक्रिय था और यह सूचना नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है।

स्थानीय नागरिक इस घटना के बाद सतर्क हैं और सुरक्षा एजेंसियों से लगातार अपडेट की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों और नागरिकों ने कहा कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं होती, तो यह सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर खतरे का कारण बन सकती थी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि पूरे जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी लगातार की जा रही है।

सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि बीकानेर जैसी सीमावर्ती जगहों में यह घटना संकेत देती है कि दुश्मन अब पारंपरिक तरीकों की बजाय तकनीकी और अंडरग्राउंड रास्तों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को और भी सतर्क रहने, स्थानीय खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने और आधुनिक निगरानी तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है।

अंततः यह खुलासा बीकानेर और आसपास के इलाके में सुरक्षा के लिए चेतावनी है कि दुश्मन तत्व लगातार अपनी रणनीति बदल रहे हैं। यह घटनाक्रम यह भी दर्शाता है कि सीमावर्ती इलाकों में उच्च सतर्कता, तकनीकी निगरानी और नागरिक सहयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरे जिले में हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करने का निर्देश जारी किया गया है।

बीकानेर में यह खुलासा न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सीमावर्ती इलाकों में तकनीकी निगरानी, ड्रोन-पैट्रोल और स्थानीय सुरक्षा नेटवर्क को और मजबूत करना अनिवार्य होगा। इस तरह यह मामला स्पष्ट करता है कि आधुनिक जासूसी और निगरानी तकनीकें कितनी संवेदनशील और खतरनाक हो सकती हैं। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और समय पर कार्रवाई ने संभवतः एक बड़े राष्ट्रीय खतरे को टाल दिया है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर भावनगर रेलवे मंडल अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर दिनांक 07 अप्रैल, 2026 (मंगलवार) को मंडल रेलवे अस्पताल, भावनगर के ऑडिटोरियम कक्ष में मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन एवं मंडल रेलवे अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार की देखरेख में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम "Together for Health – Stand with Science" रही, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. कृपा (ईएनटी सर्जन) द्वारा किया गया। उन्होंने कार्यक्रम का परिचय प्रस्तुत करते हुए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के महत्व पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर डॉ. संदीप (डीएमओ, भावनगर) एवं डॉ. मोनिका (डीएमओ, भावनगर) द्वारा विस्तृत एवं ज्ञानवर्धक व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथ्यों एवं प्रमाण-आधारित चिकित्सा (Evidence-Based Medicine) का पालन अत्यंत

आवश्यक है। साथ ही उन्होंने अफवाहों, भ्रामक जानकारी एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही गलत स्वास्थ्य सलाह से बचने की अपील की।

उन्होंने यह भी बताया कि स्वस्थ जीवनशैली के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान एवं समय-समय पर स्वास्थ्य जांच अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों एवं मरीजों को वैज्ञानिक सोच अपनाने तथा स्वास्थ्य संबंधी निर्णय विशेषज्ञों की सलाह से लेने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के समापन पर रेलवे अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा इस वर्ष की थीम पर आधारित एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। नाटक के माध्यम से "Together for Health – Stand with Science" का संदेश सरल एवं रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसने उपस्थित दर्शकों को जागरूक करने के साथ-साथ उनका मनोरंजन भी किया।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु विज्ञान आधारित सोच को अपनाने का संकल्प लिया।

"स्वस्थ समाज के लिए विज्ञान के साथ चलें।"

पश्चिम रेलवे द्वारा छह जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से विभिन्न गंतव्यों के बीच चलने वाली 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों को विस्तारित किया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1. ट्रेन संख्या 09189 मुंबई सेंट्रल–कटिहार साप्ताहिक स्पेशल को 16 मई से 25 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09190 कटिहार–मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल को 19 मई से 28 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
2. ट्रेन संख्या 09183 मुंबई सेंट्रल–बनारस साप्ताहिक स्पेशल को 20 मई से 29 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09184 बनारस–मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल को 22 मई से 31 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
3. ट्रेन संख्या 09093 उधना–अयोध्या कैंट साप्ताहिक स्पेशल को 15 मई से 31 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09094 अयोध्या कैंट–उधना साप्ताहिक स्पेशल को 16 मई से 01 अगस्त, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
4. ट्रेन संख्या 09097 उधना–अयोध्या कैंट साप्ताहिक स्पेशल को 19 मई से 28 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09098 अयोध्या कैंट–उधना साप्ताहिक स्पेशल को 20 मई से 29 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
5. ट्रेन संख्या 09465 अहमदाबाद–दरभंगा साप्ताहिक स्पेशल को 15 मई से 26 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09466 दरभंगा–अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल को 18 मई से 29 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
6. ट्रेन संख्या 09451 गांधीधाम–भागलपुर साप्ताहिक स्पेशल को 15 मई से 26 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09452 भागलपुर–गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल को 18 मई से 29 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09189, 09183, 09093, 09097, 09465 एवं 09451 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 08.04.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। ट्रेनों के समय, ठहराव एवं रेक संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

एचडीएफसी बैंक ने MCLR में कटौती की, कर्जियों के चेहरे पर आई मुस्कान

नई दिल्ली। वित्तीय बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता और आम लोगों की बढ़ती आर्थिक चिंता के बीच देश के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक ने कर्जियों के लिए राहत का बड़ा कदम उठाया है। बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में 5 बेसिस पॉइंट तक की कटौती की घोषणा की है, जो 7 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई। इस कदम का सबसे बड़ा लाभ उन ग्राहकों को मिलेगा जिनके होम लोन, ऑटो लोन या पर्सनल लोन फ्लोटिंग रेट पर आधारित हैं। इस बदलाव से उनकी मासिक किस्त यानी EMI में कमी आएगी और परिवारों के बजट पर तत्काल राहत महसूस होगी।

बैंक की ओर से जारी जानकारी के अनुसार ओवरनाइट और एक माह की MCLR को 8.15 प्रतिशत से घटाकर 8.10 प्रतिशत किया गया है, जबकि तीन माह की अवधि के लिए दर 8.25 प्रतिशत से घटकर 8.20 प्रतिशत कर दी गई है। छह माह, एक वर्ष, दो वर्ष और तीन वर्ष की MCLR यथावत रखी गई है। इस तरह बैंक की MCLR रेंज अब 8.10 प्रतिशत से 8.55 प्रतिशत के बीच आ गई है। बैंक का बेस रेट फिलहाल 8.80 प्रतिशत और PLR 17.30 प्रतिशत है। विशेषज्ञों के अनुसार, MCLR में कटौती का असर सीधे कर्ज धारकों की मासिक किस्त पर पड़ता है। MCLR यानी Marginal Cost of Funds based Lending Rate वह न्यूनतम ब्याज दर होती है, जिसके नीचे बैंक किसी भी लोन पर ब्याज नहीं ले सकता। इसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2016 में लागू किया था ताकि ऋण दरों में पारदर्शिता बनी रहे और कर्जधारक यह समझ सकें कि उनका ब्याज किस आधार पर तय हो रहा है। इस बदलाव से होम लोन लेने वाले लाखों परिवारों को अब राहत मिलेगी। मनीष और संजना, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में रहते हैं, पिछले दो साल से अपने नए फ्लैट के लिए EMI चुका रहे हैं। मनीष कहते हैं, "अभी तक हमारी EMI हर महीने बढ़ती जा रही थी। बिजली, गैस, राशन और बच्चों की स्कूल फीस का खर्च जोड़ें, तो महीने का बजट काफी तंग हो गया था। अब बैंक ने MCLR घटाकर राहत दी है। हमारी EMI में हर महीने करीब 1500-2000 रुपये की बचत होगी। यह हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है।" इतना ही नहीं, इस कदम से ऑटो लोन और पर्सनल लोन लेने वाले भी लाभान्वित होंगे। छोटे व्यवसायी और फ्रीलांसर जिनकी आमदनी साप्ताहिक या मासिक आधार पर होती है, उनके लिए भी यह राहत बड़ी मायने रखती है।

भावनगर रेलवे मंडल के जेतलसर में नवीन आरसीसी ओवरहेड टैंक का सफलतापूर्वक निर्माण एवं कमीशनिंग

यात्रियों एवं रेलवे कर्मचारियों को बेहतर जल आपूर्ति सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल द्वारा जेतलसर स्टेशन पर एक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किया गया है। पुराने सी-वेल स्टील टैंक के स्थान पर आधुनिक आरसीसी ओवरहेड (OH) टैंक का सफलतापूर्वक निर्माण एवं कमीशनिंग की गई है।

इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित आरसीसी ओवरहेड टैंक की क्षमता 2.25 लाख लीटर तथा संप (Sump) की क्षमता 2.50 लाख लीटर है। टैंक की ऊंचाई 20 मीटर है, जिससे जल आपूर्ति में पर्याप्त दबाव एवं निरंतरता सुनिश्चित की जा सकेगी।

इस कार्य पर लगभग 90 लाख रुपये की लागत आई है। परियोजना का कार्य 06 मई 2025 को प्रारंभ हुआ था तथा 08 दिसंबर 2025 को पूर्ण किया गया। इसके

पश्चात 31 मार्च 2026 को इस टैंक को सफलतापूर्वक चालू (Commission) कर दिया गया।

इस नई व्यवस्था के माध्यम से कुल 116 कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिनमें 113 स्टाफ क्वार्टर तथा 03 सेवा भवन (सीएचआई कार्यालय, जीआरपी कार्यालय एवं एससी/एसटी कार्यालय) शामिल हैं।

यह परियोजना न केवल जल आपूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ बनाएगी, बल्कि रेलवे कर्मचारियों एवं संबंधित कार्यालयों को बेहतर सुविधा प्रदान कर उनके कार्य निष्पादन में भी सहायक सिद्ध होगी।

पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल निरंतर यात्रियों एवं कर्मचारियों की सुविधाओं के उन्नयन हेतु प्रतिबद्ध है और इस प्रकार की विकासात्मक परियोजनाओं के माध्यम से आधुनिक एवं सुविधाजनक रेल अवसंरचना विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

पश्चिम रेलवे के टिकट जांच कर्मियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन

श्री अशुतोष कुमार सिंह एवं श्री लक्ष्मण कुमार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राप्त किया 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना

पश्चिम रेलवे ने आय के अनुकूलन के साथ यात्रियों में अनुशासन को सुदृढ़ करते हुए लगातार एक मानक स्थापित किया है, जिसमें अनियमितताओं को रोकने में अपने कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पश्चिम रेलवे की परिचालन दक्षता एवं सेवा उत्कृष्टता के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे के टिकट जांच कर्मियों ने सभी 6 मंडलों—मुंबई सेंट्रल, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और रतलाम तथा मुख्यालय की फ्लाइंग स्क्वाड में सराहनीय प्रदर्शन करते हुए रेलवे बोर्ड के लक्ष्यों को पार किया है।

चर्चगेट स्थित फ्लाइंग स्क्वाड के दो टिकट जांच कर्मी श्री अशुतोष कुमार सिंह एवं श्री लक्ष्मण कुमार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उप मुख्य टिकट निरीक्षक (DCTI) श्री अशुतोष कुमार सिंह ने बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा के लगभग 10,000 मामलों का पता लगाया, जिनमें बिना बुक किए गए सामान के मामले भी शामिल हैं तथा 1.17 करोड़ का जुर्माना प्राप्त किया। उन्होंने प्रतिदिन औसतन लगभग 40,000 की राशि प्राप्त की, जिसमें प्रतिदिन औसतन 34 मामलों का पता लगाया गया। इसी प्रकार, उप मुख्य टिकट निरीक्षक (DCTI) श्री लक्ष्मण कुमार ने बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा के लगभग 12,800 मामलों का पता लगाया, जिनमें बिना बुक किए गए सामान के मामले भी शामिल हैं तथा उनसे 1.08 करोड़ का जुर्माना प्राप्त किया। उन्होंने प्रतिदिन लगभग 37,500 की राशि प्राप्त की, जिसमें प्रतिदिन 40 से अधिक मामलों का पता लगाया गया।

दोनों टिकट जांच कर्मियों का यह उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी निष्ठा, नियमों एवं विनियमों के गहन ज्ञान तथा अनियमित यात्रियों के प्रभावी प्रबंधन को दर्शाता है। उनके निरंतर प्रयासों ने आय के रिसाव को कम करने तथा वास्तविक यात्रियों के लिए एक अनुशासित और निष्पक्ष यात्रा वातावरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

पश्चिम रेलवे अपने टिकट जांच कर्मियों के ईमानदार प्रयासों एवं समर्पण की सराहना करती है और यात्री अनुभव को और बेहतर बनाने तथा रेलवे की आय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टिकट जांच गतिविधियों को और सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सूरत में वैष्णव समाज का भव्य संगमः हनुमान जन्मोत्सव के साथ राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का विस्तार

सूरत में वैष्णव समाज का एक भव्य और ऐतिहासिक आयोजन उस समय देखने को मिला जब हनुमान जन्मोत्सव और परिचय सम्मेलन का संयुक्त कार्यक्रम 5 अप्रैल 2026 को सारोली स्थित लेउवा पाटीदार सांस्कृतिक भवन में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक एकता और संगठन की मजबूती का भी सशक्त उदाहरण प्रस्तुत कर गया।

कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई, जिसने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। इसके बाद दिनभर विविध धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहा। भव्य

दरबार, अखंड ज्योत और छप्पनभोग जैसे आयोजन श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे। महाप्रसाद वितरण में बड़ी संख्या में समाजजनों ने भाग लिया, जिससे पूरे परिसर में भक्ति और सेवा का अनूठा संगम देखने को मिला।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का दिल जीत लिया। वहीं राजस्थान से पधारे भजन गायक पुखराज वैष्णव और मुकेश वैष्णव के साथ स्थानीय कलाकारों ने भजनों की ऐसी प्रस्तुति दी कि पूरा माहौल भक्तिरस में डूब गया। उनके भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे और कार्यक्रम एक आध्यात्मिक उत्सव में परिवर्तित हो गया।

इस आयोजन की एक विशेष पहचान युवक-युवतियों का परिचय सम्मेलन रहा, जिसमें समाज के युवाओं को एक-दूसरे से परिचित होने और उपयुक्त जीवनसाथी चुनने का अवसर मिला। इस पहल को समाज के लोगों ने सराहा और इसे सामाजिक समरसता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

कार्यक्रम में सूरत के अलावा अंकलेश्वर, वापी, वलसाड, अहमदाबाद सहित गुजरात और राजस्थान के विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए, जिससे आयोजन का स्वरूप और भी व्यापक हो गया।

इस अवसर पर ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से वर्तमान ट्रस्ट को अखिल भारतीय स्तर का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही आनंदराज कालूदास वैष्णव को राष्ट्रीय अध्यक्ष और दीपक माण्डा को गुजरात प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

डिजिटल युग की ओर MSMEs का कदमः सूरत में चैंबर का विशेष सेशन, वर्चुअल बिज़नेस पर जोर

सूरत के कारोबारी माहौल में डिजिटल बदलाव की नई लहर को गति देने के उद्देश्य से सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित विशेष सेशन ने MSMEs के लिए एक नई दिशा तय करने का प्रयास किया। 28 मार्च 2026 को सरसाना स्थित समहति में आयोजित इस कार्यक्रम में छोटे और मध्यम उद्यमियों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के महत्व से अवगत कराते हुए उन्हें आधुनिक तकनीकों के साथ कदम मिलाने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी के स्वागत भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में केवल पारंपरिक तरीकों से व्यापार को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। उन्होंने

कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अब व्यवसाय के विस्तार का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुका है और MSMEs को इसे अपनाना ही होगा, ताकि वे बड़े बाजार तक अपनी पहुंच बना सकें और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। इस सेशन का मुख्य आकर्षण डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर केंद्रित विस्तृत प्रस्तुति रही, जिसे वीर इंफोटेक के डायरेक्टर श्रेयस गांधी ने प्रस्तुत किया। उन्होंने सरल भाषा में यह समझाया कि कैसे डिजिटल तकनीकें—जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग और वर्चुअल प्लेटफॉर्म—छोटे व्यवसायों को भी बड़े स्तर पर पहचान दिला सकती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि डिजिटल उपस्थिति न केवल ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाती है, बल्कि ब्रांड की विश्वसनीयता को भी मजबूत करती है।

कार्यक्रम के दौरान 'Websaye' प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्चुअल बिज़नेस स्थापित करने पर विशेष फोकस किया गया। प्रेजेंटेशन में यह बताया गया कि कैसे कोई भी उद्यमी अपने व्यवसाय को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर सकता है—चाहे वह अपनी वेबसाइट बनाना हो, ऑनलाइन उत्पादों का प्रचार करना हो या डिजिटल माध्यमों से ग्राहकों से जुड़ना हो। इस दौरान प्रतिभागियों को यह भी समझाया गया कि सही रणनीति अपनाकर वे कम लागत में अधिक ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं और अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। सेशन में चैंबर के ऑनरेरी ट्रेज़रर मितिश मोदी सहित कई प्रोफेशनल्स और उद्यमियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम के अंत में चैंबर के ग्रुप चेयरमैन अनिल सरावगी ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम MSMEs को समय के साथ चलने और नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।